राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जनसूत्र बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र /भोपाल /371 /18-20

वर्ष-20,अंक-21(चौबीस सालों से प्रकाशित) भोपाल,07जून,शुक्रवार 2019 पेज-8,मूल्य पांच रुपया

भोजपाल से साध्वी की राष्ट्र आराधना

जनता की ढेरों मनोकामनाओं के बीच चुनी गई मोदी सरकार की योजनाओं को जमीन पर साकार रूप देने के लिए सांसद साध्वी प्रज्ञा भारती ने जनता से मार्गदर्शन लेने की तैयारी की है। उनका कहना है कि वे मोदी सरकार की योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करेंगी। वे कहती हैं कि भोपाल से निकले अनुभव आधारित सूत्र पूरे देश के लिए उपयोगी होंगे।

भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने विकास कार्यों की सतत मानीटरिंग और उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भोपाल,07 जून(प्रेस सूचना केन्द्र)। कभी आतंकवादी कहकर प्रताड़ित की गई भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञाभारती ने वेतन न लेने की घोषणा करके पूरे देश में सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि वे भिक्षा से ही अपना जीवनयापन करेंगी। इसके साथ साथ भोपाल लोकसभा सीट के विकास कार्यों को आकार देने के लिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि वे साध्वी हैं लेकिन विकास उनका पहला एजेंडा है। मोदी सरकार ने राष्ट्र के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं उन्हें लागू करने के लिए वे जन सहयोग से अभियान चलाएंगी।

साध्वी प्रज्ञा ने सांसद बनने के बाद लोकसभा से वेतन भत्ते न लेने की घोषणा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा ये राशि देश के विकास पर खर्च की जाएगी और मैं अपना गुजारा भिक्षा मांगकर ही करूंगी। इस विचार की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहीं हैं। भारत में त्याग और तपस्या को बहुत आदर दिया जाता है इस लिहाज से ये घोषणा प्रशंसा बटोरने का हथियार भी बन गई है।

साध्वी प्रज्ञा पर मालेगांव बम धमाके में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि एनआईए की जांच में साध्वी प्रज्ञा का हाथ बम धमाके में नहीं पाया गया. इसलिए उन पर लगा मकोका और अन्य धाराएं हटा ली गई हैं. जो मुकदमे शेष हैं उनकी भी लगातार सुनवाई जारी है। कानूनी जानकारों का कहना है कि उन मुकदमों से भी वे जल्दी ही बरी हो जाएंगी।

इस बीच भोपाल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साध्वी ने तमाम विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। उनके प्रशासनिक अफसरों ने गहरी छानबीन के बाद सारी जानकारियां साध्वी तक भेज दी हैं। इनके आधार पर उन्होंने अफसरों को निर्देश भी दिए हैं जो भोपाल के विकास कार्यों को दिशा देने का काम कर रहे हैं।

जिस तरह कोलार क्षेत्र में जलसंकट गहराया उसे देखते हुए साध्वी प्रज्ञा ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे हर नागरिक को पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा है कि विकास के माहौल के बीच भोपाल को भी संवारा जाएगा।

दुनिया के बाजार में भारत की मौजूदगी बढ़ाकर संवरेगी अर्थव्यवस्था

देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है। मंदी का सिलसिला लगातार तीन तिमाहियों तक पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) केवल 5.8 फीसदी की दर से बढ़ा। यह अनुमान से कम है। वर्ष की पहली तिमाही में 8 फीसदी की वृद्धि के बाद जुलाई-सितंबर के दौरान दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से और अक्टूबर-दिसंबर की तीसरी तिमाही में 6.6 फीसदी की दर से विकसित हुई। यह मंदी का स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी पूरे वर्ष के अपने वृद्धि अनुमान को 7 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया। आंकड़े तमाम क्षेत्रों में मंदी का संकेत दे रहे हैं। इससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि मौजूदा मंदी चक्रीय न होकर ढांचागत है। अप्रैल 2019 के अंतिम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आठ प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में मंदी जारी है और इनकी वृद्धि 4.9 फीसदी से घटकर 2.6 फीसदी हो गई।

अंतिम तिमाही में धीमी वृद्धि का अर्थ यह भी है कि सरकार अब भारत के दुनिया की सबसे तेज विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा नहीं कर सकती। हालांकि यह तमगा भी कोई मायने नहीं रखता क्योंकि तमाम समान अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन भारत से बेहतर है। आर्थिक मोर्चे पर नई सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी थी हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन आंकड़ों की पिछले वर्षों से तुलना नहीं की जा सकती। मंदी के कई अन्य संकेतक भी हैं। अप्रैल में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 51.6 और 51 रहा। अगस्त और सितंबर 2018 के बाद यह सबसे धीमी वृद्धि थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का पूंजीगत वस्तु क्षेत्र भी अप्रैल में लगातार तीसरे महीने कमजोर हुआ। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी ने मई में अपनी बिक्री 22 फीसदी गिरने की बात कही। यह सात वर्षों का न्यूनतम स्तर है।

मौजूदा मंदी के कई कारक हैं। इनमें से एक कारक है अत्यधिक क्षमता की समस्या जिसके चलते निजी क्षेत्र का निवेश कमजोर पड़ता है। जबकि यह वृद्धि का एक बड़ा कारक है। निवेश में इसलिए भी कमी आई है क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की फाइनैंसिंग पर सवाल उठे हैं। यह क्षेत्र आईएलऐंडएफएस के कुछ कर्ज के डिफॉल्ट होने के बाद लगे झटके से उबरने में नाकामयाब रहा है। सरकार को इस क्षेत्र में सुधार के लिए अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी ताकि धन का प्रवाह बरकरार रखा जा सके। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र कॉर्पोरेट जगत के ऋण की फाइनैंसिंग की दृष्टि से बहुत अहम होकर उभरा है। दुनिया को लेकर भी हमें कहीं अधिक खुला नजरिया अपनाना होगा। अगर हम निर्यात पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी अतिरिक्त क्षमता की समस्या बरकरार रहेगी। देश में इतनी अधिक मांग नहीं है जितनी कि हमारी उत्पादन क्षमता हो चुकी है। अगर हम शेष विश्व को निर्यात का केंद्र बन जाएं तो इतने भर से हमारी अतिरिक्त क्षमता की समस्या दूर हो जाएगी। सरकार के पिछले कार्यकाल में अधिकांश वक्त निर्यात के मोर्चे पर प्रगति देखने को नहीं मिली। सीतारमण को आगे बढ़कर ढांचागत सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा करने पर ही प्रतिस्पर्धा बहाल की जा सकती है और निर्यात वृद्धि की सहायता से अर्थव्यवस्था को उबारा जा सकता है। इसके लिए दुनिया के बाजारों में भारत का माल बढ़ाना होगा।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
नायक बादशाह
भोपाल,07जून,शुक्रवार 2019

कमलनाथ की चुनौतियां

विकास के छिंदवाड़ा मॉडल के लिए प्रख्यात मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार को अपना कामकाज संभाले साढ़े छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। अब तक उनकी सरकार अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं संभाल पाई है। कांग्रेस का बहुचर्चित किसान कर्जमाफी का वायदा लोकसभा चुनावों के बाद भी हवा हवाई है। सरकार के वित्त विभाग ने साफ कह दिया है कि मौजूदा आर्थिक हालात में कर्जमाफी में डेढ़ साल का वक्त लग सकता है। कर्जमाफी पर सवालों के जवाब देते हुए कमलनाथ कहते रहे हैं कि मैं जानता हूं फंड की व्यवस्था कहां से करनी है। वे खुद को उद्योगपति भी बताते रहे हैं। छिंदवाड़ा में कई बड़ी कंपनियों की सोशल रिस्पांसिबिलिटी की राशि से किए गए विकास को छिंदवाड़ा माडल बताकर उन्होंने जो वाहवाही लूटी थी उसकी पोल इन छह महीनों में ही सरेबाजार खुल गई है। राज्य सरकारें जिस तरह प्रदेश के लोगों की व्यवस्था संभालती रहीं हैं उनकी तुलना में कमलनाथ सरकार ने जनता को लावारिस छोड़ दिया है। सरकार की जवाबदारियों से कन्नी काटते कमलनाथ कंजूस और मुनाफाखोर व्यापारी नजर आ रहे हैं। जिस तरह प्रदेश में तबादला उद्योग चलाया गया है उससे जनता में आक्रोश फैल रहा है। सरकार ने जो थोकबंद तबादले किए हैं और कथित तौर पर मोटा चंदा लेकर जो पोस्टिंग की हैं उनसे प्रदेश की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। इसके बावजूद स्वयं कमलनाथ और उनके मंत्री इन तबादलों को सही ठहरा रहे हैं। नौकरशाही ने सरकार के इस रवैये को देखते हुए वसूली तंत्र में जो ढील दी है उससे राजस्व आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। यही नही सरकार की फिजूलखर्ची भी बढ़ी है। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनके भक्तों के रूप में ही सरकार को करोड़ों रुपयों का राजस्व व्यय करना पड़ रहा है। प्रदेश की आय पर बेशर्मी से डाका डाल रही कमलनाथ सरकार के रवैये के कारण प्रदेश के उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। बाजार सूने पड़े हैं। एक तो रमजान का माह होने के कारण वैसे भी बाजार में कारोबार कमजोर पड़ा है उसके साथ सरकार ने विभिन्न देनदारियों को जिस बेशर्मी से बंद कर दिया है उससे बाजार में धन की आवक रुक गई है। मंडियों में किसानों का अनाज तो खरीद लिया गया है पर उनके भुगतान लंबित पड़े हैं। कई मंडियों में व्यापारियों ने अनाज खरीदकर उधारी में ही उसे बेच भी दिया। उन व्यापारियों का भुगतान अभी लंबित है और वे किसानों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कई व्यापारी तो भाग गए हैं। जिससे किसानों का पैसा डूबने की नौबत आ गई है। सरकार की ओर से किसानों को भुगतान दिलाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। कानून व्यवस्था के हाल बुरे हैं। सरेआम गुंडागर्दी और लूट का दौर शुरू हो गया है।जनता के बीच नाराजगी का नजला अफसरों को झेलना पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बावजूद सरकार में मंत्री और कार्यकर्ता लोगों से बदजुबानी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस बदला लेने वाली मानसिकता से सरकार चला रहे हैं उसे देखते हुए सरकार का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। सरकार का ये ढर्रा जारी रहा तो ये प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार होगी जिसे लोग खदेड़कर भगाएंगे। जनक्रांति की ये झलक अभी से दिखने लगी है।

विमान खरीदी में प्रफुल्ल पटेल ने लगाया चूना

फिलहाल इत्तेफाक देखें। सितंबर 2009 में एयर बस दीपक तलवार के बैंक ऑफ सिंगापुर के खाते में दो बार में 10.5 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करता है। इसी बीच एयर बस से एयर इंडिया के लिए विमान खरीद लिए जाए हैं। है ना गजब का इत्तेफाक। थोड़ा बैक ग्राउंडर देखें। एयर अरबिया 27 फरवरी 2008 को इसी बैंक के दीपक तलवार के खाते में 9.6 मिलियन डॉलर डाल देता है। एयर एशिया 1 जून को 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है। 3 जून को एमिरेट्स 23 मिलियन डॉलर और दो महीने बाद फिर से 11 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है। यहां भी इत्तेफाक होता है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते हुए उन रूटों को बंद करवा देते हैं जिससे एयर इंडिया को लाभ हो रहा था।

नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधान मंत्री बनने के बाद देश के संसाधनों की लूट के मामले में जांच तेज होने लगी है। एक मामला ये भी है। अब ई डी ने एयर इंडिया घोटाले के सिलसिले में यूपीए सरकार के दौरान नागर विमानन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल को पूछताछ के लिए 6 जून को तलब कर लिया है। ई डी के मुताबिक उसके पास पटेल और दलाली करने वाले दीपक तलवार के बीच हुई बातचीत के पुख्ता सबूत हैं,जिनमें ई मेल भी शामिल हैं। यहां आपको बताना जरूरी है कि दीपक तलवार वही कारपोरेट लॉबिस्ट है जिसे मोदी सरकार 30 जनवरी2018 को अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए दुबई से उठवा लाई थी। जांच में सामने आया कि दीपक तलवार को विदेशी एयर लाइनों से 270 करोड़ रुपए मिले थे। जिनको मनी लांड्रिंग के जरिए बाद में भारत भेजा गया। इस दलाली से तलवार ने दिल्ली में जो होटल होली डे इन लिया था जिसकी कीमत 120 करोड़ आंकी जाती है ई डी कुर्क कर चुकी है। यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि इस घोटाले पर सोनिया गांधी के यू पी ए के चेयर पर्सन होते हुए खुद को ईमानदार प्रधान मंत्री बताने वाले मनमोहन सिंह की सरकार कुंडली मार कर बैठी हुई थी। ताजा खबर तो यह भी है कि दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार के खिलाफ भी ई डी गैर जमानती वॉरंट हासिल कर चुकी है। तो क्या अचानक एन सी पी के नेता और अध्यक्ष शरद पवार का सोनिया गांधी और कांग्रेस के करीब आने और इस जांच के बीच कोई लिंक है। कारण एन सी पी के कोटे से ही प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने थे। खैर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नए नए खुलासे होते रहेंगे। फिलहाल इत्तेफाक देखें। सितंबर 2009 में एयर बस दीपक तलवार के बैंक ऑफ सिंगापुर के खाते में दो बार में 10.5 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करता है। इसी बीच एयर बस से एयर इंडिया के लिए विमान खरीद लिए गए हैं। है ना गजब का इत्तेफाक। थोड़ा बैक ग्राउंडर देखें। एयर अरबिया 27 फरवरी 2008 को इसी बैंक के दीपक तलवार के खाते में 9.6 मिलियन डॉलर डाल देता है। एयर एशिया 1 जून को 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है। 3 जून को एमिरेट्स 23 मिलियन डॉलर और दो महीने बाद फिर से 11 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है। यहां भी इत्तेफाक होता है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते हुए उन रूटों को बंद करवा देते हैं जिससे एयर इंडिया को लाभ हो रहा था। जिन एयर लाइनों ने दीपक तलवार को भुगतान किया वह सब प्रतियोगी थीं। एयर इंडिया के रूट बंद करने के बाद उनकी तो लाटरी लग गई। फिर नजराना तो बनता ही था। अब जांच इस बात की होनी है कि दीपक तलवार को मिली दलाली में से हिस्सा किस किस नेता, नौकरशाह, एयर इंडिया के अधिकारियों को मिला। इस मामले की जांच 2017 में मोदी सरकार ने शुरू करवाई थी। अभी तक तो हिस्सा पाने वाले यह दबाव बना कर बचते फिर रहे थे कि 2019 के चुनाव में उनकी सत्ता आ जाएगी तो मामला संभाल लिया जाएगा। अब मोदी के फिर से प्रधान मंत्री बनने के बाद उन सभी में खलबली मची है। कारण जांच और कानूनी कार्रवाई में सरकार फिर से बनते ही तेजी आ चुकी है। तो क्या यह एयर इंडिया घोटाला कुछ नेताओं के गले की फांस बन जाएगा। क्या कुछ बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। क्या लालू यादव की तरह कुछ और नेता आने वाले समय में जेल का भोजन पाने वाले हैं,सारे जीवन।

पेंशन योजना नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कारोबारियों को पेंशन देने के वादे पर मुहर लगा दी है, लेकिन कारोबारियों को पेंशन के लिए शर्तों पर आपत्ति है। मोदी सरकार ने 1.5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार वाले करीब 3 करोड़ जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी दी है। लेकिन पेंशन के लिए आधा अंशदान कारोबारियों को भी देना होगा, साथ ही 18 से 40 उम्र वाले कारोबारियों को पंजीयन कराने के बाद 60 साल उम्र पूरी करने पर ही पेंशन मिलेगी। कारोबारियों को अंशदान और पंजीयन के लिए उम्र सीमा पर आपत्ति है।

चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि पेंशन के लिए मंजूर मौजूदा स्वरूप के अनुसार तो कारोबारियों को मोदी सरकार के न केवल इस कार्यकाल में, बल्कि आने वाली किसी भी सरकार के तीन कार्यकाल में भी पेंशन नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह पेंशन में पंजीयन के लिए 18-40 साल उम्र सीमा है। 40 साल उम्र वाले कारोबारी अगर आज पंजीयन कराते हैं तो उन्हें 20 साल बाद पेंशन मिलेगी। 3,000 रुपये पेंशन के लिए कारोबारियों के अंशदान की शर्त भी बेमानी है क्योंकि अंशदान करने पर तो कारोबारियों के पास पेंशन के कई बेहतर विकल्प पहले से मौजूद हैं।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा कहते हैं कि अगर कारोबारियों से अंशदान ही करवाना है तो पेंशन की राशि 3,000 की बजाय कम से कम 10,000 रुपये हो। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा संगठन प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर सुझाव पर विचार करने का आग्रह करेगा।

सरप्लस बिजली के बाद भी कटौती बर्दाश्त नहीं होगी बोले कमल नाथ

भोपाल जून 4, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी कटौती होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को व्यवस्थागत कारणों से परेशानी हो, तो सरकार इसे बिल्कुल भी नजरंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती पर रोक और तकनीकी खराबियों को प्रशिक्षित अमले द्वारा तत्काल ठीक करने की चाक-चौबंद व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जून माह में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में बिजली आपूर्ति और मौजूदा समस्याओं के संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह बेहद गंभीर है कि राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बाद भी कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग अपनी संपूर्ण कार्य-प्रणाली और व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाये। बिजली उपकरणों की खरीदी में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। बेहतर उपकरण खरीदे जाएँ। उन्होंने बिजली वितरण, सुधार तथा हर स्तर पर तैनात अमले को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी उन राज्यों में जाएँ जहाँ विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि तकनीकी खराबियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर तय समय-सीमा में सुधार लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निम्न दाब विद्युत प्रणाली तथा उपभोक्ता के घरों में जाने वाले बिजली के कनेक्शन वाले विद्युत तारों का नियमित मेंटेनेंस किया जाए। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए होने वाली कटौती की पूर्व सूचना देने और आम उपभोक्ता की सुविधा से मेन्टेनेंस का समय निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कॉल सेंटर की क्षमता ब ?ाते हुए उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए मेंटेनेंस उपकरणों का आधुनिकीकरण कर बिजली सुधार की प्रक्रिया को अधिक कार्यक्षम बनाया जाये। श्री नाथ ने कहा कि मैदानी स्तर के सभी अधिकारी मेहनत और तत्परता के साथ जून माह तक सभी मेटेंनेंस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केसरी, विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह बोले बिजली सप्लाई अधिक,रखरखाव की कटौती सुधारें

भोपाल 3 जून(प्रेस सूचना केन्द्र) ।अप्रैल और मई माह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 70 करोड़ यूनिट (12 प्रतिशत) अधिक बिजली सप्लाई की गयी। इस दौरान प्रदेश में बिजली की माँग में भी औसतन 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने निर्देश दिये हैं कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी और तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियाँ आपसी समन्वय से एक साथ-एक ही बार में मेंटेनेंस का काम पूरा करें। शट डाउन की जानकारी और सूचना जन-प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन तथा जन-सामान्य को पहले से ही दी जाकर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

पावर मैनेजमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक एवं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। इस वर्ष बिजली की अधिकतम माँग 14 हजार मेगावॉट से अधिक की दर्ज हुई जिसे सफलता से पूरा किया गया। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की अधिकतम माँग 9500 मेगावॉट से ऊपर दर्ज हो रही है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह माँग 8600 मेगावॉट से ऊपर दर्ज हो रही थी।

पावर मैनेजमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल माह में 623.7 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की गयी। पिछले वर्ष इस अवधि में 552.5 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की गयी थी। मई माह में 670 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की गयी जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 600 करोड़ यूनिट थी।

प्रबंध संचालक ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही मानसून की दस्तक देने वाला है। मानसून के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई के लिये सभी फीडर का मेंटेनेंस किया जा रहा है। मेंटेनेंस के दौरान प्लान्ड शट डाउन लेना आवश्यक है। शट डाउन के दौरान संबधित क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे डिवीजन/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित अभियंताओं/तकनीकी कर्मियों को सहयोग करें।

अपनी संपदा को
सपनों के पंख लगाएं
Sage One
Financial Consultant
TANUL SHANKUSHAL
Director
+91-9425018217
tanul@sageonecapital.com
190,Hansa Complex,Zone-1
M.P.Nagar,Bhopal-462011

हीरा खदान नीलाम करने की तैयारी में कमलनाथ सरकार

भोपाल 3 जून(प्रेस सूचना केन्द्र) ।मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों, स्थाई कर्मियों, पंचायत सचिवों एवं पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के सातवें वेतनमान में महँगाई भत्ते/राहत में एक जनवरी, 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय सेवक एवं 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। एक जनवरी से 30 मार्च तक की बढ़ी हुई राशि सामान्य भविष्य-निधि खाते में जमा की जायेगी। इससे राज्य सरकार पर 1647 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय भार संभावित है।

मंत्रि-परिषद ने पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को महँगाई राहत में वृद्धि के आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति की जरूरत को भी समाप्त करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में रकबा 364 हेक्टेयर (वन भूमि) क्षेत्र में स्थित हीरा खदान को नीलाम करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में 34.20 मिलियन कैरेट हीरा खनिज के भण्डार आंकलित किये गये हैं। इसका अनुमानित भण्डारण मूल्य 60 हजार करोड़ रूपये है। इसका आधार आईबीएम द्वारा हीरा खनिज का प्रकाशित विक्रय मूल्य है। नीलामी में मध्यप्रदेश राज्य के हित में दो नई शर्तें जोड़ी गयी हैं। इसमें प्रथम नीलामी मध्यप्रदेश में ही की जाने और प्रथम नीलामी के बाद पट्टाधारी कहीं भी निर्यात एवं विक्रय करने के लिये स्वतंत्र रहेगा, शामिल है। खनिज विभाग को नीलामी की कार्यवाही शुरू करने एवं केन्द्र शासन से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया है।

9893355246
8964090155
07554726053
Royal Sun Palace
HOTEL
153, Zone-II M.P. Nagar Near Hanuman Mandir, Bhopal (M.P.)
E-mail:- royalsunpalace@gmail.com

एक्सिस बैंक के सामने बैटरियों का खजाना
Shailendra Gupta
Mob.: 9755990780
9713454209
9406543198
The Power of sight
BLAZE ENTERPRISES
Shop No. SG-17, Vijay Stambh, Infront of Axis Bank, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal | Mail : gupta_shailendra08@yahoo.co.in
251-B, Mishra Market, Ashoka Garden, Raisen Road, Bhopal
Authorised Dealer
EXIDE BATTERIES Bike, Car & Inverter
INVERTER MICROTEK STABILIZER & UPS
Deals in
CP PLUS
HIKVISION
alhua
CCTV CAMERAS

जाली नोटों के लिए चिदंबरम का जेल जाना तय

दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला खुलेगा 2019 के बाद जो शायद दुनिया मे कही नही हुआ होगा और इस महाघोटाले का मुख्य अभियुक्त है चिदंबरम सभी जानना चाहते हैं कि क्यों किया गया अचानक नोटबन्दी का फैसला और क्यों टूट गयी पाकिस्तान की अर्थव्यस्था सबूत भी बाहर आएंगे जांच हो रही है इसको पढ़कर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी

पीएम मोदी ने नोटबंदी करके इस घोटाले को रोक तो दिया, मगर उसके बाद ये बात निकल कर सामने आयी कि देश में बिलकुल असली जैसे दिखने वाले एक ही नंबर के कई नोट चल रहे थे. ये ऐसे नोट थे, जिन्हे पहचानना लगभग नामुमकिन था क्योकि ये उसी कागज पर छपे थे जिसपर भारत सरकार नोट छपवाती है.

समाचार के अनुसार डे ला रू जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, इसके साथ मिलकर तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम एक बड़ा खेल खेल रहे थे, जिसमे उनके एडिशनल सचिव अशोक चावला और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल थे.

कैसा खेला गया घोटाले का खेल ?

कहा जा रहा है कि घोटाले का प्रारम्भ 2005 में तब हुई जब वित्त मंत्रालय में अरविन्द मायाराम वित्त सचिव के पद पर थे और अशोक चावला एडिशनल सचिव के पद पर थे. कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2006 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मींटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई गयी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद मायाराम थे और चेयरमैन अशोक चावला थे, यानी दो सरकारी अधिकारी पद पर रहते हुए इस कंपनी को चला रहे थे.

बिना एसीसी के अनुमोदन के एमडी और चेयरमैन की नियुक्ति

इस प्रकार नियुक्तियों के लिए अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट (ACC) के सामने विषय को रखकर उसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है, किन्तु चिदंबरम ने भला कब नियम-कायदों की परवाह की, जो अब करते,अर्थात् ACC के सामने इन नियुक्तियों का विषय लाया ही नहीं गया और ऐसे ही इनकी नियुक्ति कर दी गयी.

इसके बाद असली खेल शुरू हुआ. इस घोटाले में चिदंबरम के दाएं व बाएं हाथ बताये जाने वाले अशोक चावला व् अरविंद मायाराम ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL), जोकि नोटों की छपाई का काम देखती है, उससे कहा कि उनकी कंपनी के साथ मिलकर सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग के सप्लायर को ढूंढो. जिसके बाद पहले से ब्लैकलिस्टेड की जा चुकी डे ला रू कंपनी से नोटों की छपाई में इस्तमाल होने वाले सिक्योरिटी पेपर को लेना जारी रखा गया.

क्या इसके लिए चिदंबरम को घूस दी गयी थी ? इस ब्रिटिश कंपनी द्वारा या पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा चिदंबरम को पैसा दिया जा रहा था ? ये जांच का विषय है. बहरहाल पहले जानते हैं कि डे ला रू को क्यों बैन किया गया था और पाक आईएसआई का इस घोटाले में क्या भूमिका है ?

डे ला रू कंपनी का खेल

दरअसल वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान नकली मुद्रा रैकेट का पता लगाने के लिए सीबीआई ने भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न बैंकों के करीब 70 शाखाओ पर छापेमारी की, तो बैंकों से ही नकली करेंसी पकड़ी गयी. जब पूछताछ के गयी तो उन बैंक शाखाओं के अधिकारियों ने सीबीआई से कहा कि जो नोट सीबीआई ने छापें में बरामद किये हैं वो तो स्वयं रिजर्व बैंक से ही उन्हें मिले हैं.

ये एक बेहद गंभीर खुलासा था क्योंकि इसके अनुसार आरबीआई भी नकली नोटों के खेल में संलिप्त लग रहा था! हांलाकि इतनी अहम् खबर को इस देश की मीडिया ने दिखाना आवश्यक नहीं समझा क्योकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी.

इस खुलासे के बाद सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के तहखानो में भी छापेमारी की और आश्चर्यजनक तरीके से भारी मात्रा में 500 और 1000 रुपये के जाली नोट पकडे गए. आश्चर्य की बात ये थी कि लगभग वैसे ही समान जाली मुद्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भारत में तस्करी से पहुँचाया जाता था.

अब प्रश्न उठा कि यह जाली नोट आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के तहखानो में कैसे पहुंच गए ? आखिर ये सब देश में चल क्या रहा था ?

जांच के लिए शैलभद्र कमिटी का गठन हुआ और 2010 में कमिटी उस वक्त चौंक गयी जब उसे ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा ही समूचे राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता को दांव पर रख कर कैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को 1 लाख करोड़ की छपाई का ठेका दिया गया था!

जाँच हुई तो ज्ञात हुआ कि डे ला रू कंपनी में ही घोटाला चल रहा था. एक षड्यंत्र के तहत भारतीय करेंसी छापने में उपयोग होने वाले सिक्योरिटी पेपर की सिक्योरिटी को घटाया जा रहा था ताकि पाकिस्तान सरलता से नकली भारतीय करेंसी छाप सके और इसका उपयोग भारत में आतंकवाद फैलाने में किया जा सके!

इस समाचार के सामने आते ही भारत सरकार द्वारा डे ला रू कंपनी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया. मगर अरविन्द मायाराम ने इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी से सिक्योरिटी पेपर लेना जारी रखा. इसे लेने के लिए उसने गृह मंत्रालय से अनुमति ली. कहा गया कि ये फाइल चिदंबरम को दिखाई ही नहीं गयी, जबकि ये बात मानने लायक ही नहीं क्योकि वित्त मंत्रालय से यदि गृहमंत्रालय को कोई भी पत्र भेजा जाता है तो पहले अप्रूवल के लिए वित्तमंत्री के सामने पेश किया जाता है.

अब ये तय माना जा रहा है कि चूँकि मोदी इस बार दुबारा पीएम बन गएहैं तो चिदंबरम का जेल जाना तय है और फिर कई अन्य गड़े मुर्दे भी बाहर आएंगे. देश को कैसे-कैसे और किस-किस ने लूटा, सबको एक-एक करके सजा होगी. कोंग्रेसी चाटुकार नौकरशाहों समेत माँ-बेटे व् कई कोंग्रेसी नेता सलाखों के पीछे पहुंचेंगे.

क्या है पाक आईएसआई की भूमिका ?

समाचार के अनुसार डे ला रू कंपनी से भारत को दिए जाने वाले सिक्योरिटी पेपर के सिक्योरिटी फीचर को कम किया जा रहा था, ये कंपनी पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी पेपर छापने का काम करती है. जिसके बाद ये आरोप लगे कि इस कंपनी द्वारा भारत का सिक्योरिटी पेपर पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से दिया जा रहा था ताकि भारत के नकली नोट छापने में पाक को सरलता हो.

यहाँ पाक आईएसआई का नाम सामने आया कि आईएसआई की ओर से कंपनी के कर्मचारियों को घूस दी जाती थी. मगर इस खेल में अरविंद मायाराम क्यों शामिल थे ? क्यों वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी से पेपर लेते रहे ?

मोदी सरकार ने लिया एक्शन

जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आयी, तब गृहमंत्री राजनाथ सिंह को ये बात पता चली की इतना बड़ा गोलमाल चल रहा था. इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी पेपर डे ला रू कंपनी से लेना बंद करवाया. ये भी सामने आया कि इस कंपनी से सिक्योरिटी पेपर काफी महंगे दाम पर खरीदा जा रहा था, यानी ये कंपनी देश को लूट रही थी और देश का वित्तमंत्रालय इस काम में विदेशी कंपनी की मदद कर रहा था!

मायाराम के इस काले कारनामे की खबर पीएमओ को हुई तो पीएमओ ने गंभीरता पूर्वक इस मामले को उठाया और मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा इसकी जांच करवाई. मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा वित्तमंत्रालय से इससे जुडी फाइल मांगी गयी. इस वक्त वित्तमंत्री अरुण जेटली बन चुके थे, मगर इसके बावजूद वित्तमंत्रालय द्वारा फाइल देने में देर की गयी.

इसके बाद ये मामला पीएमओ से होता हुआ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आया और फिर मोदी ने खुद एक्शन लिया तब जाकर मुख्य सतर्कता आयुक्त के पास फाइल पहुंची. क्या जेटली ने फाइलें देने में देर करवाई या फिर कोंग्रेसी चाटुकारों ने जो वित्तमंत्रालय तक में बैठे हैं ? ये बात साफ नहीं हो पायी.

नोटबंदी ना करते मोदी तो नकली करेंसी का ये खेल चलता ही रहता. डे ला रू से सिक्योरिटी पेपर लेना बंद किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने और पीएम मोदी ने की नोटबंदी, जिसके कारण पाकिस्तान द्वारा नकली करेंसी की छपाई बेहद कम हुई और यही कारण है कि कांग्रेस के दस वर्षों में आतंकवादी घटनाएं जो आम हो गयी थी, वो मोदी सरकार के काल में ना के बराबर हुई.

कश्मीर के अलावा देश के किसी भी राज्य में बम ब्लास्ट नहीं हो पाए. आतंकियों तक पैसा पहुंचना जो बंद हो गया था. पीएम मोदी ने जांच करवाई और मायाराम के खिलाफ मुख्य सतर्कता आयुक्त और सीबीआई द्वारा आरोप तय किये गए.

आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिस मायाराम के खिलाफ चार्ज फ्रेम किये गए हैं, उसी को राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त कर लिया. यानी एक घपलेबाज को अपना आर्थिक सलाहकार बना लिया.

वहीं अशोक चावला का नाम चिदंबरम के एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में भी सामने आया. जिसके बाद ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन व पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर पद से अशोक चावला को इस्तीफा देना पड़ा।

जुलाई 2018 में सीबीआई ने चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और 16 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आर्थिक मामलों के पूर्व केंद्रीय सचिव अशोक कुमार झा, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक चावला, संयुक्त सचिव कुमार संजय कृष्णा और डायरेक्टर दीपक कुमार सिंह, अंडर सेक्रेटरी राम शरण शामिल हैं।

इस पूरे मामले से ये बात तो साफ हो जाती है कि चिदंबरम ने देश में केवल एक या दो नहीं बल्कि जहाँ-जहाँ से हो सका, वहां-वहां से देश को लूटा. चदम्बरम व् उसके बेटे कार्ति चिदंबरम ने मिलकर खूब लूटा और इस खेल में ना केवल नौकरशाह शामिल रहे बल्कि न्यायपालिका में भी कई चिदंबरम भक्त बैठे हैं, जो आज भी उसे जेल जाने से बचाते आ रहे हैं.

कहा जा रहा है कि सभी में लूट का माल मिलकर बंटता था और यदि चिदंबरम जेल गए तो सीबीआई व् ईडी की कम्बल कुटाई उनसे एक दिन भी नहीं झेली जायेगी और वो सब उगल देंगे. यदि ऐसा हुआ तो सभी जेल जाएंगे. यही कारण है कि चिदंबरम को हर बार अग्रिम जमानत दे दी जाती है.

अब ये तय माना जा रहा है कि चूँकि मोदी इस बार दुबारा पीएम बन गएहैं तो चिदंबरम का जेल जाना तय है और फिर कई अन्य गड़े मुर्दे भी बाहर आएंगे. देश को कैसे-कैसे और किस-किस ने लूटा, सबको एक-एक करके सजा होगी. कोंग्रेसी चाटुकार नौकरशाहों समेत माँ-बेटे व् कई कोंग्रेसी नेता सलाखों के पीछे पहुंचेंगे.

(साभार).

यह समय हिन्दू विरोधियों, देशद्रोहियों को परास्त करने का है

अश्वनी मिश्र

स्वामी असीमानंद को 9 वर्ष की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद पंचकुला की विशेष एनआईए अदालत ने हाल ही में समझौता धमाके के आरोप से बरी कर दिया। अब वह सभी आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन 2010 के बाद उनका जो कठिन समय जेल में गुजरा, अमानवीय यातनाओं को सहना पड़ा, अब उस साजिश की परतें खुल रही हैं। पत्रकार अश्वनी मिश्र ने आरोप मुक्त होने के बाद स्वामी असीमानंद से विशेष बातचीत की और जाना कि कैसे संप्रग सरकार के दौरान `भगवा आतंक' जैसे जुमले गढ़कर हिन्दू समाज को आहत और अपमानित करने की साजिशें रची गई थीं। प्रस्तुत हैं उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश–

मक्का मस्जिद सहित समझौता धमाके के आरोप में आप को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब सच सामने आ चुका है और न्यायालय ने आपको बरी कर दिया है। निर्दोष साबित होने के बाद क्या कहेंगे आप ?

आखिर में सत्य की जय हुई है। इसलिए ही तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य `सत्यमेव जयते' है। इस फैसले के बाद मैं खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जिन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ना से लेकर अमानवीय यातनाएं तक दी गईं, अब उससे मुक्त होने के बाद शांति महसूस कर रहा हूं। दूसरी बात, यह हिन्दू विरोधियों की हार है। यह उनकी हार है जिन्होंने `भगवा आतंक' जैसे शब्दों को गढ़कर समस्त हिन्दू समाज को देश-दुनिया में अपमानित करने की साजिश रची। यह उनकी हार है जिन्होंने `भगवा' की पवित्रता पर लांछन लगाने का दुष्कृत्य किया। खैर, देर से ही सही, आज सच सबके सामने आ चुका है और जो इसके पीछे के साजिशकर्ता थे, उनके चेहरों से भी नकाब उतर रहा है।

आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था ? इसके पीछे प्रमुख कारण क्या मानते हैं ?

मैं हिन्दुत्व और हिन्दू समाज के लिए काम कर रहा था, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया और एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुझे गिरफ्तार करने के पीछे असल निशाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी थी। ?मेरे जरिए हिन्दू विरोधी तत्व इन संगठनों को लक्षित कर बदनाम करने की साजिश में लगे हुए थे, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए।

कथित `भगवा आतंक' के जुमले को सिद्ध करने के लिए आपको असहनीय प्रताड़नाएं दी गईं। ?इसमें कितनी सचाई है ?

बिल्कुल, यह बात सच है। मैं इसे याद करके इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझ पर असहनीय अत्याचार तो किए ही गए, अमानवीय यातनाएं तक दी गईं। लेकिन मैं टूटा नहीं, अडिग रहा।

आरोप मुक्त होने के बाद स्वामी असीमानंद अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए

आखिर में सत्य की जय हुई है। इसलिए ही तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' हैयह हिन्दू विरोधियों की हार है। यह उनकी हार है जिन्होंने 'भगवा आतंक' जैसे शब्दों को गढ़कर समस्त हिन्दू समाज को देश-दुनिया में अपमानित करने की साजिश रची।

इस पूरे मामले में तत्कालीन केंद्र सरकार, स्थानीय पुलिस, एटीएस, एनआईए एवं अन्य जांच एजेंसियों की भूमिका पर क्या कहेंगे ?

देखिए, तत्कालीन सरकार के इशारे पर मुझे फंसाने की पूरी साजिश चल रही थी और इसमें सभी जांच एजेंसियां शामिल थीं। इसलिए सरकार जो साबित कराना चाहती थी, एजेंसियां मामले को उसी ओर मो ? रही थीं। अगर यूं कहें कि एजेंसियां सरकार की कठपुलती बनकर कार्य कर रही थीं तो गलत नहीं होगा। इस दौरान मेरे ऊपर अनेक तरीके से अनैतिक दबाव डालकर एजेंसियां जो चाहती थीं, वह करा रही थीं।

राहुल गांधी द्वारा यह कहा जाना कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ी चुनौती `हिन्दू आतंकवाद' है। इसी तरह उस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार पी. चिदंबरम, सुशील शिन्दे, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के अधिकतर बयानों का केंद्र `भगवा आतंक' ही होता था। इसके पीछे क्या वजह पाते हैं ?

देखिए, कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती चली आ रही थी। कैसे एक वर्ग को और खुश करके उसे वोट में बदला जाए, इसके लिए साजिशें रची जा रही थीं। यह वही समय था, जब देश में आए दिन आतंकी हमले हो रहे थे और इनमें पकड़े जाने वाले आतंकी मुस्लिम ही होते थे। यहीं से एक साजिश रची जाती है कि कैसे एक वर्ग को `हिन्दू आतंकवाद' की आड़ में खुश किया जाए। इसलिए कुछ धमाकों के बाद हिन्दुओं को पकड़कर `भगवा आतंक' की साजिश को हवा दी गई और एक वर्ग को खुश किया गया। यह तुष्टीकरण का ही एक वीभत्स रूप था और यही प्रमुख वजह रही कि मुझे भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मैं हिन्दू समाज के बीच में काम कर रहा था, जिसके कारण मैं पहले से ही अराजक और हिन्दू विरोधी ताकतों के निशाने पर था।

`भगवा आतंक' की आड़ लेकर जिन-जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वे लोग न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित हो रहे हैं। `भगवा आतंक' को लक्षित करते हुए उस समय की सरकार के असल निशाने पर कौन था ?

जिन लोगों को `भगवा आतंक' के आरोप में गिरफ्तार किया, आज वे लोग निर्दोष साबित हो रहे हैं। और ऐसा तो होना ही है। क्योंकि झूठ एक न एक दिन जरूर खुलता है और सच सामने आता ही है। रही बात असल निशाने की तो हिन्दू विरोधियों को लग रहा था कि आने वाले दिनों में भाजपा सत्ता में आ सकती है। तो ऐसा क्या षड्यंत्र रचा जाए, जिससे भाजपा के कार्य में रुकावट उत्पन्न हो और देशभर में यह संगठन बदनाम हो जाए। ऐसी ही ताकतों ने दूसरी बड़ी साजिश रची थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की। इस सबके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था- संघ और भाजपा को मिटाने का। इसलिए हिन्दू विरोधियों द्वारा साजिश पर साजिश रची जा रही थी। मोहरा हम जैसे लोगों को बनाया गया था। हकीकत में देखें तो सच आज धीरे-धीरे सामने आ रहा है, अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो न केवल यह सदा के लिए गर्त में दबा रहता, बल्कि झूठ की बुनियाद पर हम जैसे लोगों को फांसी तक पर लटका दिया जाता। लेकिन प्रसन्नता की बात है ऐसी ताकतें अपने काम में असफल रहीं और सत्य की जीत हुई।

क्या आपने जेल से `कारवां पत्रिका' को साक्षात्कार दिया था ?

नहीं, मैंने किसी भी पत्रिका को कोई साक्षात्कार नहीं दिया था। यह पूरी तरह से झूठ है। यह पत्रिका यदि दावा करती है कि इस औपचारिक साक्षात्कार के टेप हैं तो उन्हें सामने लाना चाहिए। दूसरी बात पत्रिका की संवाददाता ने घंटों मिलने की बात कही। इसमें एक बात सही हो सकती है कि यह संवाददाता एक तय समय पर जेल में आई हो और तय समय पर जेल से बाहर गई हो, लेकिन मुझसे घंटों बात की हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। एक बार यह `संवाददाता' छद्म अधिवक्ता के तौर पर मेरे अधिवक्ता के नाम का सहारा लेकर मुझसे मिली, लेकिन उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे साक्षात्कार में लिखा गया। मैं अपने अधिवक्ता से परामर्श भी कर रहा हूं कि इस दिशा में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जांच एजेंसियां जबरदस्ती क्या कहलवाना चाहती थीं, जो आप नहीं कह रहे थे ?

जांच एजेंसियां मुझे असहनीय प्रताड़ना देकर, अमानवीयता की हदें पार कर जबरदस्ती कहलवाना चाहती थीं कि आतंकी गतिविधियां `रा.स्व. संघ और भाजपा' के इशारे पर हुईं। वे मुझसे कई और झूठ बोलने के लिए मजबूर करती थीं। इसलिए जांच एजेंसियां मेरे साथ अमानवीयता की पराकाष्ठा तक गई। इसी कड़ी में एक पत्रिका ने एक झूठ देश-दुनिया में प्रसारित किया। एक समाचार को बिल्कुल झूठा छापा और हल्ला मचाया।

न्यायालय में दिया गया आपका एक बयान मीडिया की सुर्खियां बना था, जबकि यह बयान पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए था। क्या यह भी कोई साजिश थी ?

देखिए, तब कांग्रेस की सरकार थी तो समझ सकते हैं कि जांच एजेंसियां किसके इशारों पर काम कर रही थीं। जो बयान लीक हुआ, वह एक साजिश थी और यह सब पुलिस हिरासत में ही हुआ। इससे सबकुछ समझा जा सकता है। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे ऊपर विभिन्न तरह के दबाव डाले जा रहे थे। शारीरिक यातनाएं दी जा रही थीं। परिवार के लोगों को हानि पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी, खासकर मां को। पर मैं सत्य पर अडिग रहा।

कथित `भगवा आतंक' पर तो खूब शोर सुनाई दिया पर `इस्लामी आतंक' की बात आते ही यह शोर थम जाता है। उल्टे तब कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। क्या कहेंगे आप इस पर ?

बिल्कुल, यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर वे सच कह देंगे तो मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा और उनसे छिटक जाएगा। इसलिए हिन्दू समाज को बदनाम करते रहो, उसके खिलाफ बोलते रहो, उनके मान बिन्दुओं पर प्रहार करते रहो। ऐसा करने से एक वर्ग खुश होगा और वोट देगा। देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही `भगवा आतंक' जैसा शब्द गढ़ा गया था। हिन्दुओं का दमन करने के लिए हिन्दू विरोधियों ने इस `जुमले' का सहारा लेकर इसे साजिश का रूप दिया। हकीकत में देखें तो हिन्दू समाज कभी भी आतंकवाद में संलिप्त नहीं रहा, उसके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया हो, ऐसा कोई भी उदाहरण 5 हजार साल के इतिहास में देखने को नहीं मिलता।

गिरफ्तारी से पहले आप जनजाति समाज के उत्थान और जागरण का काम कर रहे थे। क्या इस दिशा में फिर से सक्रिय होंगे ?

जो काम मैं पहले से ही कर रहा हूं, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही हिन्दू समाज की सेवा है और यह कार्य मैं अंतिम समय तक करता रहूंगा। वनवासी क्षेत्रों में हिन्दू विरोधियों द्वारा वनवासी समाज को बरगलाने, उनका कन्वर्जन करने का जो घृणित काम किया किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए मैं पहले की तरह ही काम करूंगा। हां, यह सही है कि मेरे कार्य की वजह से ही मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। हिन्दू शक्तियों का दमन करने के लिए ही सभी हिन्दू विरोधी एक हुए थे। वे चाहे मुस्लिम, ईसाई, कांग्रेस एवं वामपंथी ही क्यों न रहे हों! क्योंकि मैं वनवासी क्षेत्रों में हिन्दू विरोधियों की साजिश को स्वजनों की `घर वापसी' के जरिए नाकाम कर रहा था। इससे हिन्दू समाज के विरोध में जो साजिशें रची जा रही थीं, उन पर पानी फिर रहा था। इसलिए यह प्रतिशोध लिया गया। निन्संदेह, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने पर बहुत बड़े-बड़े संकट आते हैं, लेकिन धर्म और सत्य के तेज से वह न केवल क्षीण होते हैं बल्कि सत्य की जीत होती है। मेरे संन्यासी एवं आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य मानव जीवन का मंगल, उनकी सेवा करना है। और यह कार्य मैं लगातार करता रहूंगा।

(पांचजन्य से साभार)

महात्मा गांधी को संघ ने कभी खारिज नहीं किया

डॉ. मनमोहन वैद्य

संघ और गांधीजी के संबंध कैसे थे, इसे तथ्यात्मक रूप से जाने बिना अनेक लोग धारणाएं बना लेते हैं। संघ के बारे में अनेक स्कॉलर कहलाने वाले लोग भी बिना अध्ययन या एक विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखे साहित्य के आधार पर विचार व्यक्त करते हैं जिनका सत्य से कोई लेना-देना नहीं होता

चुनाव के दौरान एक दल के नेता ने कहा कि इस चुनाव में आपको गांधी या गोडसे के बीच चुनाव करना है। एक बात मैंने देखी है। जो गांधी जी के असली अनुयायी हैं। वे अपने आचरण पर अधिक ध्यान देते हैं, वे कभी गोडसे का नाम तक नहीं लेते। संघ में भी गांधी जी की चर्चा तो अनेक बार होती देखी है पर गोडसे के नाम की चर्चा मैंने कभी नहीं सुनी। परंतु अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए गांधी जी के नाम को भुनाने के लिए, ऐसे-ऐसे लोग गोडसे का नाम बार-बार लेते हैं जिनका आचरण और जिनकी नीतियों का गांधी जी के विचारों से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं दिखता। वे तो सरासर असत्य और हिंसा का आश्रय लेने वाले और अपने स्वार्थ के लिए गांधी जी का उपयोग करने वाले ही होते हैं।

एक दैनिक के सम्पादक ने, जो संघ के स्वयंसेवक भी हैं, कहा कि एक गांधीवादी विचारक के लेख हमारे दैनिक में प्रकाशित हो रहे हैं। उस सम्पादक ने यह भी कहा कि उन गांधीवादी विचारक ने लेख लिखने की बात करते समय यह कहा था कि संघ के और गांधीजी के संबंध कैसे थे, यह मैं जानता हूं, फिर भी मैं उन कुछ पहलुओं के बारे में लिखूंगा जिनके बारे में आप अनजान हैं। यह सुन कर मैंने प्रश्न किया कि संघ और गांधीजी के संबंध कैसे थे, यह वे विचारक सही में जानते हैं? लोग बिना जाने, बिना अध्ययन किए अपनी धारणाएं बना लेते हैं। संघ के बारे में तो अनेक विद्वान, स्कॉलर कहलाने वाले लोग भी पूरा अध्ययन करने का कष्ट किए बिना या, सिलेक्टिव अध्ययन के आधार पर या एक विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखे साहित्य के आधार पर ही अपने विद्वतापूर्ण विचार व्यक्त करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि इन विचारों का सत्य से कोई लेना-देना नहीं होता है।

महात्मा गांधी के कुछ मतों से घोर असहमति होते हुए भी, उनके संघ से संबंध कैसे थे, इस पर उपलब्ध जानकारी पर नजर डालनी चाहिए। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जनाधार को व्यापक बनाने के शुद्ध उद्देश्य से मुसलमानों के कट्टर और जिहादी मानसिकता वाले हिस्से के सामने उनकी शरणागति से सहमत न होते हुए भी, आजादी के आंदोलन में सर्वसामान्य लोगों को सहभागी होने के लिए उन्होंने चरखे जैसा सहज उपलब्ध अमोघ साधन और सत्याग्रह जैसा सहज स्वीकार्य तरीका दिया, वह उनकी महानता है। ग्राम स्वराज्य,

स्वदेशी, गोरक्षा, अस्पृश्यता निर्मूलन आदि उनके आग्रह के विषयों से भारत के मूलभूत हिंदू चिंतन से उनके लगाव और आग्रह के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उनका स्वयं का मूल्याधारित जीवन अनेक युवक-युवतियों को आजीवन व्रतधारी बनकर समाज की सेवा में लगने की प्रेरणा देने वाला था।

1921 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों सत्याग्रहों में डॉक्टर हेडगेवार सहभागी हुए थे। इस कारण उन्हें 19 अगस्त 1921 से 12 जुलाई 1922 तक और 21 जुलाई,1930 से 14 फरवरी, 1931 तक, दो बार सश्रम कारावास की सजा भी हुई।

महात्मा गांधी को 18 मार्च, 1922 को छह वर्ष की सजा हुई। तब से उनकी मुक्ति तक प्रत्येक महीने की 18 तारीख गांधी दिन के रूप में मनाई जाती थी। 1922 के अक्तूबर मास में गांधी दिन के अवसर पर दिए गए भाषण में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि आज का दिन अत्यंत पवित्र है। महात्मा जी जैसे पुण्यश्लोक पुरुष के जीवन में व्याप्त सद्गुणों के श्रवण एवं चिंतन का यह दिन है। उनके अनुयायी कहलाने में गौरव अनुभव करने वालों के सिर पर तो उनके इन गुणों का अनुकरण करने की जिम्मेदारी विशेषकर है।

1934 में वर्धा में श्री जमनालाल बजाज के यहां जब गांधी जी का निवास था तब पास ही संघ का शीत शिविर चल रहा था। उत्सुकतावश गांधी जी वहां गए, संघ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और स्वयंसेवकों के साथ उनका वार्तालाप भी हुआ। वार्तालाप के दौरान जब उन्हें पता चला कि शिविर में अनुसूचित जाति से भी स्वयंसेवक हैं, और उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सब भाईचारे के साथ स्नेहपूर्वक साथ रहते हैं, सारे कार्यक्रम साथ करते हैं, तब उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की।

स्वतंत्रता के पश्चात जब गांधी जी का निवास दिल्ली में मैला ढोने वाले समाज की कॉलोनी में था, तब सामने मैदान में संघ की प्रभात शाखा चलती थी। सितम्बर में गांधी जी ने प्रमुख स्वयंसेवकों से बात करने की इच्छा व्यक्त की और सम्बोधित किया- बरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्व. जमनालाल बजाज मुझे शिविर में ले गए थे। मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। तब से संघ काफी बढ़ गया है। मैं तो हमेशा से यह मानता हूं कि जो भी संस्था सेवा और आत्म-त्याग के आदर्श से प्रेरित है, उसकी ताकत बढ़ती ही है। लेकिन सच्चे रूप में उपयोगी होने के लिए त्याग भाव के साथ ध्येय की पवित्रता और सच्चे ज्ञान का संयोजन आवश्यक है। ऐसा त्याग, जिसमें इन दो चीजों का अभाव हो, समाज के लिए अनर्थकारी सिद्ध हुआ है।(यह सम्बोधन (गांधी समग्र वाङ्मय) के खंड 89 में 215-217 पृष्ठ पर प्रकाशित है।)

30 जनवरी, 1948 को तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी मद्रास में एक कार्यक्रम में थे, जब उन्हें गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। उन्होंने तुरंत ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी को टेलीग्राम द्वारा अपनी शोक संवेदना भेजी। उसमें श्री गुरुजी ने लिखा, प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभूति की दुखद हत्या का समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। वर्तमान कठिन परिस्थिति में इससे देश की अपरिमित हानि हुई है। अतुलनीय संगठक के तिरोधान से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे पूर्ण करने और जो गुरुतर भार कंधों पर आ पड़ा है, उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करें।

गांधी जी के प्रति सम्मान रूप शोक व्यक्त करने के लिए 13 दिन तक संघ का दैनिक कार्य स्थगित करने की सूचना उन्होंने देशभर के स्वयंसेवकों को दी। दूसरे ही दिन 31 जनवरी, 1948 को श्री गुरुजी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा। उसमें वे लिखते हैं- कल मद्रास में वह भयंकर वार्ता सुनी कि किसी अविचारी भ्रष्ट-हृदय व्यक्ति ने पूज्य महात्मा जी पर गोली चलकर उस महापुरुष के आकस्मिक-असामयिक निधन का नीरयृण कृत्य किया। यह निंदा कृत्य संसार के सम्मुख अपने समाज पर कलंक लगाने वाला हुआ है।

ये सारी जानकारी 'Justice on Trial' नामक पुस्तक में और श्री गुरुजी समग्र में उपलब्ध है। 6 अक्तूबर, 1969 में महात्मा गांधी जी की जन्मशताब्दी के समय महाराष्ट्र के सांगली में गांधी जी की प्रतिमा का श्री गुरुजी के द्वारा अनावरण किया गया। उस समय श्री गुरुजी ने कहा-आज एक महत्वपूर्ण व पवित्र अवसर पर हम एकत्र हुए हैं। सौ वर्ष पूर्व इसी दिन सौराष्ट्र में एक बालक का जन्म हुआ था। उस दिन अनेक बालकों का जन्म हुआ होगा, पर हम उनकी जन्म-शताब्दी नहीं मनाते। महात्मा गांधी जी का जन्म सामान्य व्यक्ति के समान हुआ, पर वे अपने कर्तव्य और अंतःकरण के प्रेम से परमश्रेष्ठ पुरुष की कोटि तक पहुंचे। उनका जीवन अपने सम्मुख रखकर, अपने जीवन को हम उसी प्रकार ढालें। उनके जीवन का जितना अधिकाधिक अनुकरण हम कर सकते हैं, उतना करें।

लोकमान्य तिलक के पश्चात महात्मा गांधी ने अपने हाथों में स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्र संभाले और इस दिशा में बहुत प्रयास किए। शिक्षित-अशिक्षित स्त्री-पुरुषों में यह प्रेरणा जगाई कि अंग्रेजों का राज्य हटाना चाहिए, देश को स्वतंत्र करना चाहिए और स्व के तंत्र से चलने के लिए जो कुछ मूल्य देना होगा, वह हम देंगे। महात्मा गांधी ने मिट्टी से सोना बनाया। साधारण लोगों में असाधारणत्व निर्माण किया। इस सारे वातावरण से ही अंग्रेजों को हटना पड़ा।

वे कहा करते थे-मैं कट्टर हिन्दू हूं, इसलिए केवल मानवों से ही नहीं, सम्पूर्ण जीवमात्र से प्रेम करता हूं। उनके जीवन व राजनीति में सत्य व अहिंसा को जो प्रधानता मिली, वह कट्टर हिंदुत्व के कारण ही मिली।

जिस हिंदू-धर्म के बारे में हम इतना बोलते हैं, उस धर्म के भवितव्य पर उन्होंने -फ्यूचर ऑफ हिंदुइज्म- शीर्षक से अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखा है- हिंदू धर्म यानी न रुकने वाला, आग्रह के साथ बढ़ने वाला, सत्य की खोज का मार्ग है। आज यह धर्म थका हुआ-सा, आगे जाने की प्रेरणा देने में सहायक प्रतीत होता अनुभव में नहीं आता। इसका कारण है कि हम थक गए है, पर धर्म नहीं थका। जिस क्षण हमारी यह थकावट दूर होगी, उस क्षण हिंदू धर्म का भारी विस्फोट होगा जो भूतकाल में कभी नहीं हुआ, इतने बड़े परिमाण में हिंदू धर्म अपने प्रभाव और प्रकाश से दुनिया में चमक उठेगा। महात्मा जी की यह भविष्यवाणी पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है।

देश को राजकीय स्वतंत्रता चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। उसी भांति इस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए कि कोई किसी का अपमान न कर सके, भिन्न-भिन्न पंथ के, मत के लोग साथ-साथ रह सकें। विदेशी विचारों की दासता से अपनी मुक्ति होनी चाहिए। गांधी जी की यही सीख थी। मैं गांधी जी से अनेक बार मिला हूं। उनसे बहुत चर्चा भी की है। उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, उन्हीं के अध्ययन से मैं यह कह रहा हूं। इसीलिए अंतःकरण की अनुभूति से मुझे महात्मा जी के प्रति नितांत आदर है। गुरुजी कहते हैं, महात्मा जी से मेरी अंतिम भेंट सन् 1947 में हुई थी। उस समय देश को स्वाधीनता मिलने से शासन-सूत्र संभालने के कारण नेतागण खुशी में थे। उसी समय दिल्ली में दंगा हो गया। मैं उस समय शांति प्रस्थापना करने का काम कर रहा था। गृह मंत्री सरदार पटेल भी प्रयत्न कर रहे थे और उस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। ऐसे वातावरण में मेरी महात्मा गांधी से भेंट हुई थी। महात्मा जी ने मुझसे कहा-देखो यह क्या हो रहा है? मैंने कहा-यह अपना दुर्भाग्य है। अंग्रेज कहा करते थे कि हमारे जाने पर तुम लोग एक-दूसरे का गला काटोगे। आज प्रत्यक्ष में वही हो रहा है। दुनिया में हमारी अप्रतिष्ठा हो रही है। इसे रोकना चाहिए। गांधीजी ने उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में मेरे नाम का उल्लेख गौरवपूर्ण शब्दों में कर, मेरे विचार लोगों को बताए और देश की हो रही अप्रतिष्ठा रोकने की प्रार्थना की। उस महात्मा के मुख से मेरा गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ, यह मेरा सौभाग्य था। इन सारे सम्बन्धों से ही मैं कहता हूं कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए।

मैं जब वडोदरा में प्रचारक था तब (1987-90) सहसरकार्यवाह श्री यादवराव जोशी का वडोदरा में प्रकट व्याख्यान था। उसमें श्री यादवराव जी ने महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान के साथ उल्लेख किया। व्याख्यान के पश्चात कार्यालय में एक कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि आज आपने महात्मा गांधी जी का सम्मानपूर्वक जो उल्लेख किया, वह क्या मन से किया था? इस पर यादवराव जी ने कहा कि मन में ना होते हुए भी, मैं केवल बोलने वाला कोई राजकीय नेता नहीं हूं। जो कहता हूं, मन से ही कहता हूं। फिर उन्होंने समझाया कि जब किसी व्यक्ति का हम आदर-सम्मान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके सभी विचारों से हम सहमत होते हैं। एक विशिष्ट प्रभावी गुण के लिए हम उन्हें याद करते हैं, आदर्श मानते हैं। जैसे पितामह भीष्म को हम उनकी प्रतिज्ञा की दृढ़ता के लिए अवश्य स्मरण करते हैं, परंतु राज सभा में द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय वे सारा अन्याय मौन बैठे देखते रहे, इसका समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कट्टर और जिहादी मुस्लिम नेतृत्व के संबंध में गांधी जी के व्यवहार के बारे में घोर असहमति होने के बावजूद, स्वतंत्रता आंदोलन में जनसामान्य को सहभागी होने के लिए उनके द्वारा दिया गया अवसर, स्वतंत्रता के लिए सामान्य लोगों में उनके द्वारा प्रज्ज्वलित की गई ज्वाला, भारतीय चिंतन पर आधारित उनके अनेक आग्रह के विषय, सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्त किया जन आक्रोश-ये उनका योगदान निश्चित ही सराहनीय और प्रेरणादायी है।

इन सारे तथ्यों को ध्यान में लिए बिना संघ और गांधी जी के संबंध पर टिप्पणी करना असत्य और अनुचित ही कहा जा सकता है। ग्राम विकास, सेंद्रिय कृषि, गोसंवर्धन, सामाजिक समरसता, मातृभाषा में शिक्षा और स्वदेशी अर्थ व्यवस्था एवं जीवनशैली-ऐसे महात्मा गांधी जी के प्रिय एवं आग्रह के क्षेत्रों में संघ स्वयंसेवक पूर्ण मनोयोग से सक्रिय हैं। इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती है। उनकी पावन स्मृति को विनम्र आदरांजलि।

(लेखक रा.स्व. संघ के सह सरकार्यवाह रहे हैं)

इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार का प्रोत्साहन

देवांग्शु दत्ता

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए तमाम नीतिगत कदम उठाए गए हैं। इन वाहनों के साथ कई लाभ जुड़े हैं। वे शून्य-उत्सर्जन के साथ शोर भी बहुत कम करते हैं। प्रति किलोमीटर उपभोग के संदर्भ में विद्युत ऊर्जा काफी सस्ती पड़ती है। इन वाहनों के इंजन में आंतरिक दहन (आईसी) इंजनों की तुलना में गतिशील हिस्से कम होते हैं। इस वजह से उनका रखरखाव आसान होता है और उनके ठप हो जाने की आशंका कम होती है। हाइब्रिड इंजनों के लिए भी यह बात सही है क्योंकि उसमें आईसी इंजन को कम क्षति होती है।

आमचुनाव में तेल लाबी की ओर से हराने के लिए दिए गए भारी चंदे के बावजूद भाजपा सत्ता में लौट आई है। इससे देश में बिजली आधारित वाहनों का प्रचलन तय हो गया है।

हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें इनका एक नकारात्मक पहलू है। करों में कटौती के बावजूद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की कीमतें आईसी इंजन वाले वाहनों से काफी अधिक होती हैं। परिचालन लागत कम होने से इसकी थोड़ी भरपाई होती है फिर भी फर्क अधिक है। सुरक्षा का मुद्दा भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने पर उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। लिथियम-आयन बैटरी की आग बुझाए जाने के कई घंटे बाद भी शॉर्ट-सर्किट होने से दोबारा आग भड़क सकती है। अग्निशमन विभाग को बैटरी चालित वाहनों में लगी आग बुझाने के लिए नए सिरे से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में अधिक वक्त लगता है। यहां तक कि फास्ट रिचार्ज करने में भी कम-से-कम 20 मिनट लग जाते हैं। बैटरी की अदला-बदली एक जल्दबाजी वाला विकल्प है लेकिन वह भी पेचीदा काम है। अलग-अलग वाहनों को अलग तीव्र एवं सुस्त चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत होती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी ढांचागत आधार तैयार करना एक चुनौती है। देश भर में 60,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। इससे एक अंदाजा मिलता है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए कितने चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ेगी? बैटरी चालित वाहनों की सर्विसिंग, रखरखाव और मरम्मत के लिए अपने कर्मचारियों को नए सिरे से प्रशिक्षित करने की भी जरूरत होगी। मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये वाले फेम-2 कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई थी। हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) के पहले कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल, 2015 को 895 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी। दो साल की अवधि वाले फेम-1 कार्यक्रम की मियाद कई बार बढ़ाई गई।

फेम-2 के लिए सरकार ने तीन साल की अवधि तय की है। इसका लक्ष्य 10 लाख दोपहिया, 5 लाख तिपहिया, 55 हजार चार-पहिया और 7,000 बसों को मदद देना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री निम्न आधार होने से बहुत तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसाइटी का दावा है कि वर्ष 2018-19 में 6.3 लाख इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और 1.26 लाख दोपहिया वाहन और करीब 3,600 यात्री कारों की बिक्री हुई। यह 1.9 करोड़ से अधिक दोपहिया-तिपहिया वाहनों की बिक्री के चार फीसदी से भी कम है और 30 लाख से अधिक कारों के एक फीसदी से भी कम है।

फेम-2 कार्यक्रम के तहत 2019-20 में 1500 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,000 करोड़ रुपये और 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 35,000 चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 1.5 लाख रुपये और 20,000 हाइब्रिड चार-पहिया वाहनों को 13,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा 7,090 ई-बसों को 50-50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2018 के मसौदे में वर्ष 2023 तक पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में 25 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों के पहुंचाने का लक्ष्य है और हरेक तीन किलोमीटर पर बैटरी एक्सचेंज सेंटर और चार्जिंग स्टेशन बनाने का उद्देश्य है। दिल्ली में सालाना करीब सात लाख नए वाहनों का पंजीकरण होता है।

दिल्ली की इस नीति में फेम-2 कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा भी काफी कर-छूट एवं सब्सिडी देने का जिक्र है। एक इलेक्ट्रिक दोपहिया को 22,000 रुपये तक की सब्सिडी देने के अलावा बैटरी बदलने पर भी अलग से सब्सिडी मिलेगी। बीएस-2 या बीएस-3 मानक वाले दोपहिया वाहनों को कबाड़ में देने पर 15,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स, पंजीकरण, एमसीडी पार्किंग शुल्कों से छूट मिलती है और ई-ऑटो या ई-कैब के हरेक फेरे पर 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। दिल्ली सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने जा रही है।

शहरी इलाकों में हरेक तीन किलोमीटर और राजमार्गों पर हरेक 25 किलोमीटर दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन मुहैया कराने का लक्ष्य देखते हुए फेम-2 के तहत चार्जिंग स्टेशनों को लाइसेंस-मुक्त किया गया है। हरेक चार्जिंग स्टेशन पर फास्ट चार्ज और स्लो चार्ज के लिए अलग प्लग-प्वाइंट लगाने की जरूरत होती है। फास्ट चार्ज सिस्टम में एक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम और एक चाडेमो प्लग लगा होता है जिसमें 200-1000 वोल्ट के 50 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं। वहां 380-480 वोल्ट के 22 किलोवाट क्षमता वाले टाइप-2 एसी फास्ट चार्जर की भी जरूरत होती है। इसके अलावा स्लो चार्जिंग के भी दो प्वाइंट- भारत एसी 001 और भारत डीसी 001 रखने होते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के लिए इनकी कीमतों का कम होना और बैटरियों की लागत में कमी आना जरूरी है। चार्ज स्टेशनों और दक्ष सेवा कर्मचारियों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। मौजूदा रुख के हिसाब से भारत में दोपहिया एवं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले रफ्तार पकड़ने की संभावना है और किराये की सवारी के तौर पर लोग इनका अधिक इस्तेमाल करेंगे। हालांकि माहौल बदलने और कीमतों में कमी आने पर निजी उपयोग भी बढ़ सकता है। परमाणु बिजली आने से तो तस्वीर ही बदल जाएगी।

बेरोजगारी को भयावह बताने छोड़ दी कई कंपनियां

बताया जाता है कि सरकार ने पिछले साल राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी नीति में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के विलय का निर्णय ले लिया है। दोनों ही विभाग केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आते हैं। एक नया राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन गठित किया जाएगा और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव के रूप में मुख्य सांख्यिकीविद की भूमिका समाप्त की जाएगी। नए सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की अध्यक्षता सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव के पास होगी।

इस मौके पर सांख्यिकी से जुड़े विभागों का पुनर्गठन खास महत्त्व रखता है। अतीत में इस पर करीबी नजर नहीं थी और इसे केवल अफसरशाही के फेरबदल या प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में देखा गया। परंतु हालिया घटनाएं बताती हैं कि इस प्रक्रिया पर बारीक नजर रखनी होगी क्योंकि आधिकारिक तौर पर आंकड़े जुटाने और उन्हें मंजूरी दिलाने का यही एक तरीका है। वहीं दूसरी ओर यह केंद्र सरकार की सांख्यिकी मशीनरी में बेहतर तालमेल लाने वाला भी बन सकता है। आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़े अब कहीं अधिक तेज गति से आ सकते हैं और पूरी व्यवस्था कितने किफायती ढंग से काम कर रही है इसका आकलन किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों की दलील है कि मौजूदा व्यवस्था ऐसी है जिसकी बदौलत दोहराव और प्रचुरता हो रही है। उनका कहना है कि अफसरशाही को सुसंगत बनाकर, उनका विलय करके और उन्हें एक नेतृत्व के अधीन लाकर काम को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। एक सामान्य सिद्धांत के रूप में देखें तो केंद्र सरकार की समूची अफसरशाही में ऐसे बदलाव की आवश्यकता है।

परंतु भारत सरकार की सांख्यिकी मशीनरी का मामला अपने आप में विशिष्ट है। मौजूदा हालात में इसकी संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। डेटा तैयार करने की प्रक्रिया की स्वायत्तता को लेकर तमाम सवाल पूछे जाते रहे हैं। इनकी शुरुआत सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों से हुई लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं हैं। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों की नई शृंखला से जुड़े सवालों का जवाब देने के क्रम में गत वर्ष एक बैक सीरीज की घोषणा की गई थी लेकिन इससे उन आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर संदेह और अधिक गहरा हो गया। इन आंकड़ों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के आंकड़ों को घटा दिया गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आंकड़ों को बढ़ा दिया गया।

ये चर्चाएं उस समय सार्वजनिक होकर जोर पकड़ने लगीं जब वरिष्ठ सांख्यिकीविदों ने इस बात को लेकर त्यागपत्र दे दिया कि सरकार एनएसएसओ के रोजगार संबंधी आंकड़े जारी करने में विफल रही है। ये आंकड़े बता रहे थे कि बेरोजगारी 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन बातों के बीच कुछ लोगों की चिंता थी कि सरकार आधिकारिक आंकड़ों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रही है। भारत में इससे पहले इसे लेकर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी। कुछ सप्ताह पहले एनएसएसओ की एक अन्य रिपोर्ट ने दिखाया कि एमसीए 21 के डेटाबेस में काफी कंपनियां तलाशी नहीं जा रही हैं। वे बंद हो गई हैं अथवा अन्य क्षेत्रों में कारोबार कर रही हैं।

ऐसे में यह स्पष्ट है कि सांख्यिकी को सुसंगत बनाने के बजाय विश्वसनीयता बहाल करने, पारदर्शिता लाने और स्वायत्तता सुनिश्चित करने पर जोर होना चाहिए। खेद की बात है कि मंत्रालय के सचिव के अधीन एक नया और एकीकृत संगठन इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। पर्यवेक्षक इसे डेटा की विश्वसनीयता में सुधार का संकेत नहीं मानेंगे। उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल बढ़ते जाएंगे।

उत्पादकता बढ़ाएगा जमीन को पट्टे पर देने का कानूनी हक

सुरिंदर सूद

जमीन को पट्टे पर देने को कानूनी रूप से वैध बनाना अब कृषि सुधार का महज संभावित लाभदायक पहलू ही नहीं रहा बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता बन चुका है। आजादी के बाद देश में भूमि स्वामित्व की सामंतवादी व्यवस्था ध्वस्त करने और जमीन का मालिकाना हक रखने वाले और नहीं रखने वालों के बीच असमानता कम करने के लिए कृषि सुधार किए गए थे। लेकिन अब हमें इस बात की जरूरत है कि खेती-योग्य जमीन के स्वामित्व का दायरा बढ़ाया जाए ताकि कृषि कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सके। खेती नहीं करने वाले भूस्वामियों के बेकार पड़े खेतों का भी कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है।

उत्तराधिकार कानूनों के चलते भू-स्वामित्व में लगातार बंटवारा होते जाने से अधिकांश जोतों का आकार इतना छोटा हो चुका है कि कृषि पर आश्रित एक औसत परिवार की जरूरतें उससे पूरी नहीं हो सकती हैं। वर्ष 2010-11 की पिछली कृषि जनगणना ने दिखाया था कि करीब 85 फीसदी परिचालक भूमि स्वामित्व का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है और इसका औसत आकार तो महज 1.15 हेक्टेयर ही है। इससे भी बुरी बात यह है कि छोटे एवं सीमांत कृषि जोतों की संख्या सालाना 15 लाख से 20 लाख तक बढ़ रही है। अधिकांश मामलों में ये जोत भी अविभक्त नहीं हैं और दूर-दूर फैले छोटे आकार के खेतों में बंटे हुए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जमीन के इन छोटे टुकड़ों पर खेती करना आर्थिक रूप से और परिचालन के स्तर पर भी अव्यवहार्य हो चुका है। यह खेती की लाभप्रदता में कमी और कृषि क्षेत्र में चौतरफा व्याप्त आर्थिक तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है।

खेतों के बंटवारे की प्रक्रिया तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि उत्तराधिकार कानूनों को संशोधित कर उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विभाजन को नियंत्रित न किया जाए। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है लिहाजा इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए एक पारदर्शी एवं कानूनी रूप से वैध भूमि पट्टा बाजार का विकास सबसे व्यावहारिक तरीका लगता है। भूमि पट्टेदारी को वैध दर्जा देने से किसानों के बीच कृषि कार्यों के लिए जमीन का विनिमय संभव हो सकेगा और उनके मालिकाना हक पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही छोटे एवं बिना जुताई वाले खेतों के मालिक अपने खेत अपने पड़ोसियों या अन्य छोटे किसानों को पट्टे पर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे वहीं छोटे एवं सीमांत किसान पट्टे पर खेत लेकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे।

गांवों में नहीं रहने वाले अधिकतर भूस्वामी पट्टेदारी को कानूनी मान्यता नहीं होने से अपना कब्जा खो देने के डर से अपने खेतों को पट्टे पर देने में संकोच करते हैं। यह कुछ राज्यों में लागू पुराने काश्तकारी कानूनों का परिणाम है जिनमें बंटाई या पट्टे पर खेती कर रहे काश्तकारों को जमीन का स्थायी अधिकार दे दिया गया था। इस वजह से करीब 2.5 करोड़ हेक्टेयर जुताई योग्य जमीन बंजर पड़ी हुई है। इसके अलावा अब काश्तकारी सौदे जुबानी या गुप्त होने लगे जिसमें किसी भी पक्ष को सुरक्षा नहीं होती है।

इसके अलावा बंटाईदारों समेत सभी अनौपचारिक पट्टाधारकों को दूसरी तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सस्ती दरों पर संस्थागत कर्ज न ले पाना, फसल बीमा, आपदा राहत और सरकार की तरफ से भूस्वामियों को दी जाने वाली तमाम अन्य सुविधाएं एवं सब्सिडी नहीं मिल पाना सबसे अहम हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसान कृषि ऋण माफी और कृषक आय समर्थन जैसी सरकारी योजनाओं के भी पात्र नहीं हो पाते हैं। इस तरह जमीन की उपज बढ़ाने और खेती की सक्षमता बढ़ाने के उपायों में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई कारक भी नहीं रह जाता है।

इन अधिकांश अड़चनों को जमीन पट्टेदारी को कानूनी रूप से वैध बनाकर दूर किया जा सकता है। नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग पहले ही आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम का प्रारूप बना चुका है जो राज्यों के लिए अपने अलग भूमि पट्टेदारी कानून बनाने की राह दिखा सके। इस मसौदा कानून को वर्ष 2016 में ही राज्यों के बीच वितरित कर दिया गया था लेकिन गिने-चुने राज्यों ने ही इसके अनुरूप अपने कानूनों में बदलाव करने की रुचि दिखाई है। प्रस्तावित कानून कृषि-भूमि के मालिक और काश्तकार किसान दोनों के ही वैध हितों को सुरक्षित करने की बात करता है। पट्टेदारी के सौदों को आपसी सहमति से अंतिम रूप देने की अनुमति देने से यह कानून पट्टे की अवधि खत्म होने पर भूमि का स्वामित्व उसके असली मालिक के पास लौट आएगा।

इसके अलावा यह मसौदा कानून पट्टाधारकों को दूसरे किसानों को मिलने वाले सभी लाभ पाने का हकदार बनाने के लिए भूस्वामियों के बराबर दर्जा देता है। गौर करने लायक एक और खासियत यह है कि जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में निवेश करने वाले काश्तकारों को पट्टे की मियाद खत्म होने पर उनके निवेश का अनुप्रयुक्त मूल्य वापस मिल जाएगा। इस प्रावधान से पट्टे वाली भूमि के समतलीकरण, मृदा स्वास्थ्य उन्नतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह नीति आयोग के आदर्श कानून की तर्ज पर अपने यहां भूमि पट्टेदारी कानून लाने में राज्यों की हिचकिचाहट कृषि समुदाय के हितों का ध्यान नहीं रख रही है।

पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों की दुर्दशा को देखने के बाद देस के अन्य राज्यों ने सबक लिया है।

अर्थव्यवस्था में भारी फेरबदल करेगी मोदी सरकार

टी. एन. नाइनन

राजधानी नई दिल्ली के जानकार लोगों के बीच एक चर्चा यह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल पहले से अलग होगा। पिछले पांच वर्ष उन्होंने अपनी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत करने में खपाए। कहा जा रहा है कि अब वह अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अब वह ऐसे कदम उठाने को तैयार हैं जो वह पांच साल पहले करने को तैयार नहीं थे। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गति चाहिए। तिमाही आर्थिक वृद्धि गिरकर 6 फीसदी से नीचे आ चुकी है और पांच साल के निचले स्तर पर है। पूरे वर्ष की वृद्धि का हाल भी वही है जहां से मोदी सरकार ने शुरुआत की थी। पाठकों को याद होगा कि शुरुआत में दो अंकों में वृद्धि हासिल करने की बात कही गई थी। हकीकत उससे कोसों दूर है। भारत सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा गंवा चुका है और चीन उससे आगे हो गया है।

मैंने दो सप्ताह पहले भी इस स्तंभ में लिखा था कि यह बहुमुखी चुनौती है। कृषि, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में तमाम चुनौतियां सामने हैं। राजकोषीय और मौद्रिक नीति अलग समस्या है। दोनों ही जगह गुंजाइश बहुत सीमित है। व्यापक दलील यह हो सकती है कि पहले दौर के आर्थिक सुधारों ने जो गति प्रदान की थी, वह 15 वर्ष की निष्क्रियता के कारण गंवा दी गई। अब एक नई लहर की आवश्यकता है। क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? बदलाव की शुरुआत मोदी से ही करनी होगी। अब तक उन्होंने वृहद आर्थिक मुद्दों में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अधिक रुचि ली है। चुनाव नतीजे बताते हैं कि वह इसमें सफल रहे हैं। अब यह अनदेखी जारी नहीं रह सकती। प्रधानमंत्री को अपने समक्ष मौजूद प्रमुख नीतिगत कारकों की समझ पैदा करनी होगी। इसमें रुपये के बाह्य मूल्य को लेकर सरकार का रुख और देश के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में इसकी उपयोगिता भी शामिल है। शुरुआत करें तो रुपये की मजबूती की मान्यता को त्यागना होगा।

बैंक और कंपनियां अब तक जिस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बेहतर वृद्धि हासिल करना बहुत मुश्किल है। यह ऐसा दौर है जब ढेर सारे कारोबारी नए निवेश पर विचार करने के लिए पुराने कर्ज को कम करने में व्यस्त हैं और उपभोक्ता ईएमआई पर केंद्रित हैं। सरकारें मौजूदा बचत का काफी हिस्सा खपा रही हैं और बाजार की ब्याज दरों को गिरने से रोक रही हैं। इसका असर नकदी की आवक और भविष्य के निवेश पर हो रहा है। बीते वर्ष कर राजस्व लक्ष्य से पीछे रह गया, उसे गति देने की आवश्यकता है। मंदी के दौर में यह कैसे होगा?

संक्षेप में कहें तो बतौर नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश व्यापार और उद्योग मामलों के प्रभारी पीयूष गोयल के समक्ष काफी कुछ करने को है। दोनों को जल्द से जल्द अपना एजेंडा लागू करना होगा। इसके साथ ही मध्यम अवधि के नीतिगत लक्ष्य तय करने होंगे ताकि पूंजी का किफायती इस्तेमाल हो सके, श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाया जा सके और बुनियादी ढांचा ऐसा हो जो उद्योग और व्यापार को प्रभावी सहयोग दे सके। इसके लिए व्यवस्थित सोच अपनाने की जरूरत है।

सुर्खियों में आने के लिए तात्कालिक कदम उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। वित्त मंत्री वस्तु एवं सेवा कर दरों को तार्किक बनाने और उनकी तादाद कम करने से शुरुआत कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों में कटौती कर सहयोग करना चाहिए। विनिवेश को गति देने की जरूरत है, इसकी शुरुआत एयर इंडिया से हो सकती है। परंतु अगर इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना है तो यह सवाल लाजिमी तौर पर उठेगा कि खरीदार कहां हैं? क्या इसमें तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशी खरीदारों का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए?

इन सब बातों के अलावा कृषि, जल संबंधी अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे मसलों का क्या जो हमारे समक्ष मुंह बाये खड़े हैं? ये तीनों मंत्रालय नए मंत्रियों के हाथ में हैं। ऐसे में यह सवाल बना रहेगा कि आखिर उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा?

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. aloksinghai67@gmail.com सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।